



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 38-2016/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, MARCH 14, 2016 (PHALGUNA 24, 1937 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 14 मार्च, 2016

संख्या 6/एस.टी.-1/ह0अ0 6/2003/धा0 59 /2016. — चूंकि, राज्य सरकार की संतुष्टि हो गई है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण लोकहित में तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक है ;

अब, इसलिए, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 59 की उप-धारा (1) के परन्तुक के साथ पठित उक्त उप-धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पूर्व नोटिस की शर्त को अभिमुक्त करते हुए, प्रथम फरवरी, 2016 से, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची ख में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) में, अनुसूची ख में, खाना 1 तथा 2 के नीचे, क्रम संख्या 3ग तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात्:-

"3घ	हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा फरीदाबाद जिले में आयोजित सूरज कुण्ड क्राफ्ट मेला, सूरज कुण्ड के परिसर में पर्यटकों को अनियमित व्यापारियों द्वारा बेचे गये सभी माल।"
-----	---

रोशन लाल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग ।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 14th March, 2016

No.6/ST-1/H.A. 6/2003/S.59/2016. - Whereas, the State Government is satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action in public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 59 read with the proviso to said Sub-section of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in Schedule B appended to the said Act, with effect from 1st February, 2016, by dispensing with the condition of previous notice, namely:-

Amendment

In the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003), in Schedule B, under columns 1 and 2, after serial number 3C and entry thereagainst, the following serial number and entry thereagainst shall be inserted, namely:-

“3D	all goods sold by casual traders to the visitors in the premises of Surajkund Crafts Mela, Surajkund in Faridabad District organized by the Haryana Tourism Department”.
-----	--

ROSHAN LAL,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.

हरियाणा सरकार

गृह विभाग

आदेश

दिनांक 14 मार्च, 2016

क्रमांक 2/7/96-2 गृह गो0.— चूंकि, हरियाणा के राज्यपाल, राज्य में सम्भावित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संतुष्ट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन जिलाधीशों को तुरन्त कार्यवाही करने हेतु प्राधिकृत करना आवश्यक है।

इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार की शक्तियां हरियाणा राज्य के सभी जिलाधीशों द्वारा भी उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर, दिनांक 12/03/2016 से 11/06/2016 तक तीन मास की अवधि के लिए प्रयोग की जा सकेंगी।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 14 मार्च, 2016.

पी0 के0 दास,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग ।

HARYANA GOVERNMENT
SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT

Order

The 14th March, 2016

No. 248-SW(4)-2016.—The State Level Committee constituted under the Chairmanship of Chief Secretary to Government, Haryana for reviewing the implementation of the Prime Minister New 15 point Programme for the Welfare of Minorities and the Multi Sectoral Development Programme in Minority Concentration Blocks in the State. As resolved by the State Level Committee the 15 Point Programme and Multi Sectoral Development Programme may be reviewed on a quarterly basis at the level of Additional Chief Secretary/Principal Secretary to Government,

Haryana, Social Justice and Empowerment Department and the proceedings may be put up to the State Level Committee whenever, it meets. In future, the quarterly progress may be sent to Ministry of Minority Affairs, Government of India in time.

Chandigarh :
The 11th March, 2016.

KUMAR SUNIL GULATI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Social Justice and Empowerment Department.

HARYANA GOVERNMENT
SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT

Notification

The 14th March, 2016

No. 247-SW(4)-2016.— In partial modification of Haryana Government, Notification bearing No. 124-SW(4)-2012, dated 23rd February, 2012, Notification No. 292-SW(4)-2014, dated 5th August, 2014 and Notification No. 865-SW(4)-2015 dated 31st August, 2015 the Governor of Haryana is pleased to include the following Members of Parliament as a Non-Official Members in the State Level Committee for implementation of the Prime Minister's New 15 Point Programme for the Welfare of Minorities and the Multi-Sectoral Development Programme in Minority Concentration Districts in the State :

- | | | |
|----|--|--------|
| 1. | Sh. Charanjeet Singh Rori, Member Parliament, Sirsa
11, Meena Bagh, New Delhi
Ph. No. 011-23061077
Mob. 09013869140 | Member |
| 2. | Sh. Ramesh Chander Kaushik, Member Parliament, Sonipat
30, Canning Lane, New Delhi
Mob. 09013869143, 09416069997 | Member |
| 3. | Kumari Selja, Rajya Sabha Member,
7, Moti Lal Nehru Marg, New Delhi
Ph. No. 011-23018269, 23018074
Mob. 09013181062 | Member |

The functions of the Committee shall be as under :

- (i) Review & monitor progress of the Prime Minister's New – 15 Point Programme.
- (ii) To consider & recommend to Ministry of Minority Affairs, Government of India, New Delhi the proposals under the Multi-Sectoral Development Plans for the Minority Concentration Blocks.
- (iii) Review & monitor the implementation of the progress Multi-Sectoral Development Plans for the Minority Concentration Blocks.
- (iv) Ensure that quarterly progress reports on Prime Minister's New – 15 Points Programme & Multi – Sectoral Development Plans for Minority Concentration Blocks are sent to Ministry of Minority Affairs, Government of India by the 15th day of the next quarter.

The Committee will meet at least once in a year.

Chandigarh :
The 11th March, 2016.

KUMAR SUNIL GULATI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Social Justice and Empowerment Department.

हरियाणा सरकार

अक्षय ऊर्जा विभाग

आदेश

दिनांक 14 मार्च, 2016

संख्या 22/52/2005-5 विद्युत.— ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52), की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, अक्षय ऊर्जा विभाग, आदेश संख्या 22/52/05-5 विद्युत, 29 जुलाई, 2005 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

हरियाणा सरकार, अक्षय ऊर्जा विभाग, आदेश संख्या 22/52/05-5 विद्युत, दिनांक 29 जुलाई, 2005 में पैरा 1, “सौर जल तापीय प्रणाली आज्ञापक उपयोग” का लोप कर दिया जाएगा ।

अंकुर गुप्ता,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अक्षय ऊर्जा विभाग ।

HARYANA GOVERNMENT**RENEWABLE ENERGY DEPARTMENT****Order**

The 14th March, 2016

No.22/52/2005-5 Power.— In exercise of the powers conferred by section 18 of the Energy Conservation Act, 2001 (Central Act 52 of 2001), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Renewable Energy Department, Order No.22/52/05-5Power, dated the 29th July, 2005, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Renewable Energy Department, Order No. 22/52/05-5Power, dated the 29th July, 2005, **Para 1, “Mandatory use of Solar Water Heating Systems”** shall be omitted.

ANKUR GUPTA,
Principal Secretary to Government Haryana,
Renewable Energy Department.

हरियाणा सरकार

अक्षय ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 14 मार्च, 2016

संख्या 19/4/2016-5 विद्युत-& हरियाणा सरकार सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सौर ऊर्जा नीति, 2016 तैयार की है। इस नीति को प्रभावी करने के लिए, विभिन्न नीतियों, नियमों और विनियमों में आवश्यक संशोधन, जहां आवश्यक हो, शीघ्रता से संबंधित विभाग द्वारा किया जायेगा ।

हरियाणा सौर ऊर्जा नीति, 2016

अध्याय-1

परिचय**1.1 सौर ऊर्जा ही क्यों**

शुरुआत करने के लिए हमें रहने की जरूरत है। यदि विकल्प हो तो हम एक सतत तरीके से अच्छी तरह से रह सकते हैं । सौर ऊर्जा को भविष्य के लिए ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया है । भारत में विशेष रूप में यह अंदाज लगाया जा सकता है कि कोयले का भंडार वर्ष 2040-50 से अधिक समय तक नहीं रहेगा । दुनिया भर में तेल का भंडार भी घट रहा है और अपने आप में प्रदूषण के कारकों के साथ जुड़ा हुआ है ।

सौर ऊर्जा:-

- स्थायी और अक्षय

- कम रखरखाव की आवश्यकता
- पर्यावरण के अनुकूल है, इसलिए वहाँ ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से बचाव और कम कार्बन उत्सर्जन है ।
- निःशुल्क ऊर्जा का अपार स्रोत और अन्य गैर नवीनकरणीय स्रोतों की जगह सबसे अच्छा है ।
- कीमत के उतार-चढ़ाव से बचाव में मदद करता है ।
- परिस्थिति की प्रणालियों और आजीविका बचाता है ।
- यह विभिन्न प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और पूरी तरह से न केवल भारत में ग्रामीण सेट अप में, लेकिन यह शहरी आबादी के लिए कई मदों के लिए फिट बैठता है ।
- सौर पैनलों को आसानी से लगाया जा सकता है और इसके लिए हमेशा बिजली या गैस ग्रिड की स्थापना की आवश्यकता नहीं है ।
- सौर ऊर्जा बिजली मिश्रण के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है ।

1.2 भारतीय परिदृश्य

आर्थिक विकास, बढ़ती समृद्धि, शहरीकरण की बढ़ती दर और प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत के हिसाब से आज भारत के लिए एक सुनहरा समय है। जिससे पूरे देश में ऊर्जा का उपयोग बढ़ गया है। देश का उद्देश्य सौर प्रौद्योगिकी के विकास और समावेशी भर में सौर ऊर्जा विकास सुनिश्चित करना है ।

विशेष रूप से]

- 2022 तक भारत में एक लाख मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है ।
- वर्ष 2017 तक भारत में प्रतिवर्ष चार गुना सौर प्रणालियां लग जायेंगी ।
- भारत सरकार के लक्ष्यों को जो 2022 के अंत तक लगभग 175 गीगावॉट के लिए कुल अक्षय क्षमता लगेगा गठन किया है ।
- जिसमें लघु पनबिजली से बायोमास बिजली से पवन ऊर्जा से 60 गीगावॉट, 10 गीगावॉट और 5 गीगावॉट शामिल है ।

1-3 हरियाणा-प्रतिस्पर्धात्मक लाभ

हरियाणा राज्य भारत के उत्तरी भाग में स्थित है, जिसमें 253.5 लाख लोगों की आबादी है और 44212 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है । खाद्य उत्पादन, प्रति व्यक्ति आय, औद्योगिक विकास, उत्कृष्ट परिवहन और संचार सुविधाओं के मामले में राज्य आसानी से देश का सबसे उन्नत राज्यों में से एक के रूप में जाना जाता है ।

यह है:-

- एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था
- विश्वस्तरीय बुनियादी सुविधाएं
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक विशाल बाजार के लिए पहुंच
- निवेशक अनुकूल नीतियां
- सामंजस्यपूर्ण श्रम संबंध
- सामरिक स्थान
- रेल, सड़क और हवाई सम्पर्क
- दक्ष जनशक्ति
- तेजी से शहरीकरण और औद्योगीकरण
- कायदा और कानून

1-4 सत्ता के लिए विजन-मिशन

एक पर्यावरण जहां ऊर्जा और बिजली की मांग तेज गति से बढ़ रही है, राज्य अक्षय ऊर्जा को बढ़ाकर पूरे देश के अभियान का हिस्सा बनकर शामिल होना चाहता है ।

राज्य साल में 300 से अधिक पूर्ण सूर्य दिवस के कारण उच्च सौर विकिरण स्तर से धन्य है और इसलिए अप्रयुक्त तथा कभी खत्म न होने वाले सौर ऊर्जा का दोहन करना चाहता है ।

राज्य इसलिए करना चाहता है:

- हरित और स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना
- देश में निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के भागीदारों के लिए सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने हेतु अनुकूल वातावरण बनाना
- उक्त को व्यावहारिक निवेश के प्रोत्साहन तथा प्रेरित करने हेतु माहौल बनाना

- राज्य के सभी नागरिकों में पर्यावरण चेतना का प्रसार करना
- ऊर्जा क्षेत्र की एक विकेन्द्रीकृत और विविध प्रबन्धन के लिए निशाना लगाना
- अक्षय सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी को बढ़ावा देने हेतु सतत कार्य करना
- वर्तमान में इसके 0.25 प्रतिशत सौर अक्षय खरीद बाध्यता लक्ष्य को प्राप्त करना तथा जोकि 2021-22 तक कम से कम 8 प्रतिशत से ऊपर पहुंच जायेगा
- अंततः सही ऊर्जा मिश्रण के साथ संचालित राज्य के एक प्रौद्योगिकी बनाने के लिए

1.5 शीर्षक और प्रवर्तन

- 1.5.1 यह नीति हरियाणा सौर ऊर्जा नीति, 2014 का स्थान लेगी।
- 1.5.2 यह नीति हरियाणा सौर ऊर्जा नीति, 2016 के रूप में जानी जाएगी।
- 1.5.3 नीति इसकी अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगी और जब तक नई पालिसी अधिसूचित नहीं की जाती लागू रहेगी।
- 1.5.4 राज्य सरकार किसी भी तकनीकी सफलता को ध्यान में रखते हुए या किसी भी विद्युत अधिनियम की विसंगतियों को हटाने के लिए या भारत सरकार की नीति/राज्य विद्युत नियामक आयोग के आदेश के मध्येनजर इस नीति की समीक्षा कर सकता है।

1-6 उद्देश्य

इस नीति का उद्देश्य इस प्रकार है:-

- 1.6.1 सौर ऊर्जा का उपयोग करके राज्य में ग्रीन और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है।
- 1.6.2 राज्य में सौर ऊर्जा आधारित बिजली परियोजनाओं की स्थापना व उन्हें बढ़ावा देने में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी के साथ-साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के लिए अनुकूल परिस्थितियों का सृजन।
- 1.6.3 सामाजिक आर्थिक परिवर्तन उत्प्रेरित करने और विकास में क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए बंजर भूमि व गैर उत्पादक उपयोग भूमि का प्रयोग करना।
- 1.6.4 रोजगार प्रदान करना और युवाओं के कौशल को बढ़ाना।
- 1.6.5 एक उपयुक्त निवेश का माहौल बनाना जिससे कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म (सीडीएम) के लाभों का लाभ उठाने और ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) के उत्सर्जन में कमी हो।
- 1.6.6 सौर उत्कृष्टता के केंद्रों और तकनीकी पेशेवरों के संघ जो अनुप्रयुक्त अनुसंधान व स्वदेशी और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के व्यावसायीकरण के साथ सौर ऊर्जा उत्पादन और उपकरणों के प्रयोग की दिशा में काम करेगा।
- 1.6.7 राज्य के सभी नागरिकों विशेष रूप से युवाओं और स्कूल जा रहे बच्चों में पर्यावरण चेतना का प्रसार करना।
- 1.6.8 अक्षय सौर ऊर्जा का विकेन्द्रीकरण, विविधीकरण और अक्षय सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना।

1-7 सौर अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आर.पी.ओ.)

अब तक हरियाणा नियामक आयोग ने 2021-22 तक 3 प्रतिशत सौर अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता को निर्धारित किया है।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार वर्ष 2022 तक एक लाख मेगावाट सौर ऊर्जा का महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त करने की योजना बना रहा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय सौर अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आर.पी.ओ.) को मौजूदा 3 प्रतिशत से 8 प्रतिशत करने की योजना मंत्रालय बना रहा है। जिसके हिसाब से हरियाणा राज्य को वर्ष 2021-22 तक 3200 मेगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करने होगी।

सौर अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता को प्राप्त करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित पहल की है:-

- क. जमीन की स्थापना मेगावाट पैमाने पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की मुहिम शुरू की।
- ख. अपनी भूमि पर हरियाणा पावर जेनरेशन निगमों द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना।
- ग. सौर ऊर्जा निगम हरियाणा लिमिटेड(एस.यू.एन. हरियाणा) के माध्यम से सौर पार्कों का विकास।
- घ. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों की योजनाओं जैसे वी.जी.एफ. स्कीम, बेरोजगार युवाओं/किसानों के लिए योजना व राष्ट्रीय विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (एन.वी.वी.एन.एल.)/एन.टी.पी.सी. की बंडलिंग स्कीम के तहत बिजली की खरीद।
- ङ. नहर तट पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना।
- च. छत ग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्र नेट मिटरिंग के माध्यम से लगाना।

छ. सरकारी भवनों के समूह पर छत ग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना ।

अध्याय -2

धरातल आधारित ऊर्जा परियोजनाएं

2-1 धरातल आधारित मेगावाट स्केल ऊर्जा संयंत्र

हरियाणा बिजली खरीद केन्द्र खुली प्रतिस्पर्धा बोली प्रक्रिया के माध्यम से हरियाणा विद्युत नियामक आयोग के द्वारा सांकेतिक दर पर स्वतंत्र बिजली उत्पादकों से सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए निविदा आमंत्रित करेगा । स्वतंत्र बिजली उत्पादक स्टेट ग्रिड कोड के अनुसार परियोजनाएं स्थापित करेंगे ।

स्वतंत्र बिजली उत्पादक ग्रिड के साथ कनेक्टिविटी के लिए सबसे नजदीक का सब-स्टेशन उचित वोल्टेज पर इस्तेमाल करेंगे ।

2-2 क्षमता आरक्षण

हरियाणा बिजली खरीद केन्द्र द्वारा निविदित सभी निविदाओं में 20 प्रतिशत का आरक्षण 1 मेगावाट से 2 मेगावाट की लघु परियोजनाओं के लिए आरक्षित रहेगी ।

2-3 बिजली खरीद केन्द्र सौर ऊर्जा खरीद बाध्यता के लक्ष्य से 200 मेगावाट तक ज्यादा बिजली खरीद करेगा ।

2-4 जो उत्पादक 1 मेगावाट से 2 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र हरियाणा में लगाता है तो उसको हरियाणा से बाहर लगाये गये संयंत्रों से 2 प्रतिशत की कीमत की वरीयता दी जायेगी ।

2-5 सौर पार्क का विकास

परियोजना डेवलपर्स से महत्वपूर्ण निवेश लाने के लिए, सौर अक्षय खरीद बाध्यता (आर.पी.ओ.) जनादेश को पूरा करने, सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए व अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए राज्य में सौर पार्कों को स्थापित किया जायेगा । उसके लिए एक संयुक्त उद्यम कम्पनी एच.एस.आई.आई.डी.सी. और एच.पी.जी.सी.एल. द्वारा सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड हरियाणा (एस.यू.एन. हरियाणा) गठित की गई है । यह कम्पनी हरियाणा के विभिन्न हिस्सों में निजी बिजली उत्पादक के लिए सोलर पार्क/सौर ऊर्जा संयंत्र भूमि का विकास करेगी ।

2-6 नहर ओवरहेड्स पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना

नहरों पर मेगावाट पैमाने पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की संभावना का पता लगाया जाएगा । यह केवल पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराने में ही मदद नहीं करेगा बल्कि यह पानी के वाष्पीकरण को कम करने में भी मदद करेगा । नहर ओवरहेड्स की साइट सिंचाई विभाग, हरियाणा के परामर्श से ज्ञात किया जाएगा । इसके लिए हरियाणा बिजली खरीद केन्द्र बीडर का चयन खुली बोली के आधार पर एक अलग निविदा द्वारा करेगा । सौर फोटोवोल्टेइक ऊर्जा संयंत्रों की बोली लगाने वाले का खुली बोली के माध्यम से हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एच.आर.सी) द्वारा तय लेवलाइज्ड टैरिफ पर अधिकतम छूट की पेशकश के आधार पर चयन किया जाएगा । सौर ऊर्जा संयंत्र से पूरी बिजली तय टैरिफ में हरियाणा की विद्युत वितरण लाइसेंसधारी द्वारा खरीदी जाएगी । बोलीदाता को वो सारे लाभ दिये जायेंगे जो एक धरातल आधारित योजना के लिए दिये जाते हैं जिसके लिए राज्य द्वारा बिना शुल्क के बिजली निकास की सुविधा दी जायेगी चाहे वो कितनी भी दूरी पर हो । स्वतंत्र बिजली उत्पादक जिन्होंने लघु नहर पर लघु पन बिजली योजना लगा रखी है उनके आबंटित नहर किनारे/शीर्ष पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा ।

2-7 पंचायत भूमि को पट्टे/किराये पर

हरियाणा सरकार सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए कम से कम 30 साल तक सौर ऊर्जा निगम या सीधा पंचायत के द्वारा (सरकार की नीति के अनुसार) उचित दर पर सुविधा प्रदान करेगी ।

2-8 धरातल आधारित ग्रिड सौर ऊर्जा परियोजनाएं (प्रक्रिया)

2-8-1 राज्य में मेगावाट पैमाने पर सौर विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए हरियाणा बिजली खरीद केन्द्र प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से बोलियां आमंत्रित करेगा व खुली प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर बिजली खरीद की दर निर्धारित करेगा । निविदा दस्तावेज में निहित मापदंडों के मूल्यांकन के आधार पर परियोजना डेवलपर्स को आशय पत्र जारी करेगा तथा समय-समय पर खरीद दर के बारे में अक्षय ऊर्जा विभाग को सूचित करेगा ।

आशय पत्र जारी होने के बाद प्रोजेक्ट डेवलपर अक्षय ऊर्जा विभाग/हरेडा की एकल खिड़की के माध्यम से आवश्यक मंजूरी के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा ।

2-8-2 सौर ऊर्जा परियोजनाओं सरकार के लैंड सीलिंग एक्ट का पर्वालोकन से बार होगा ।

अध्याय-3

छत आधारित बिजली परियोजनाएं

3-1 छत ग्रिड/आफ ग्रिड सौर ऊर्जा परियोजनाएं

राज्य में सौर छत आधारित सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के माध्यम से सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए अच्छी क्षमता है । तदनुसार, उद्योगों सार्वजनिक एवं निजी संस्थानों, स्कूलों, कालेजों, वाणिज्यिक एवं सामाजिक संस्थानों/प्रतिष्ठानों,

चैरीटेबल ट्रस्ट के भवनों, हस्पतालों और आवासीय भवनों की छतों पर अपनी कैप्टिव उपयोग/नैट मीटर विनियमन के तहत 1 किलोवाट से 1 मेगावाट की क्षमता के ग्रिड से जुड़े व 50 किलोवाट तक की क्षमता के आफ-ग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

छत आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कैपिटल/उत्पादन आधारित सब्सीडी/प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा।

वर्ष 2021-22 तक 1600 मेगावाट छत सौर ऊर्जा संयंत्र लगाये जायेंगे।

3-2 सार्वजनिक/निजी भवनों की छतों के क्लस्टर

अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता को प्राप्त करने के लिए लगाये जाने वाले धरातल आधारित मेगावाट स्तर के सौर विद्युत संयंत्रों की कुल क्षमता का एक निश्चित प्रतिशत (जो समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा) छत आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए रखा जायेगा। इसके लिए अक्षय ऊर्जा विभाग स्वतंत्र बिजली उत्पादकों से 250 किलोवाट से 1 मेगावाट के सार्वजनिक/निजी भवनों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए हरियाणा बिजली खरीद केन्द्र द्वारा अन्तिम न्यूनतम निर्धारित खरीद दर पर निविदा आमंत्रित करेगा। बिजली उत्पादक द्वारा इस पालिसी की घोषणा के 4 साल के भीतर लगाई गई योजनाओं से पूरी बिजली हरियाणा सरकार की किसी संस्था या हरियाणा बिजली खरीद केन्द्र द्वारा खरीदी जायेगी। वैकल्पिक रूप से डेवलपर इस बिजली को अपने परिसर में नेट मीटरिंग के साथ इस्तेमाल कर सकता है और फालतू बिजली हरियाणा बिजली खरीद केन्द्र या सरकार के दूसरी संस्था को हरियाणा बिजली खरीद केन्द्र द्वारा अन्तिम न्यूनतम निर्धारित खरीद दर पर बेच सकता है या वो किसी तीसरी पार्टी को हरियाणा विद्युत नियामक आयोग के विनियमों के तहत बेच सकता है।

सभी ज्यादा से ज्यादा वह अतिरिक्त लाभ जो संभव हो छत आधारित सौर ऊर्जा उत्पादक को दिये जायेंगे।

छत आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए भवन योजना स्वीकृति प्राधिकरण से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। छत आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र आर.पी.ओ./आर.ई.सी. के योग्य होंगे।

3-3 फ़ैक्ट्री फ़ुड्स

कैप्टिव उपयोग के लिए वह तीसरी पार्टी को खुले उपयोग के तहत लगाये गये छत आधारित के लिए बिजली निकासी के प्रबन्ध जैसे वोल्टेज बढ़ाने, सिंगरोनाइजिंग उपकरण, मिटरिंग विद्युत उत्पादक द्वारा हरियाणा विद्युत नियामक आयोग के द्वारा निर्धारित किये गये तकनीकी विशिष्टियों, दिशा-निर्देशों व विनियमों के अनुसार किया जायेगा। तथापि यदि समर्पित ट्रांसमिशन लाइन की आवश्यकता होती है तो वह धरातल आधारित ऊर्जा संयंत्र की प्रक्रिया के अनुसार प्रदान की जायेगी।

3-4 नरवक/कफ़र लक़्ज़ो/फ़ैक्ट्री/कस्टमर, अर्ध-वैद्युत/कल

3.4.1 छत आधारित सौर ऊर्जा परियोजनाएं (मेगावाट स्केल तथा लघु परियोजनाएं) नेट मिटरिंग कार्यक्रम सहित अक्षय ऊर्जा विभाग द्वारा लागू की जायेगी।

3.4.2 एक बार प्रस्ताव के अनुमोदन (एल.ओ.आई. जारी) होने के बाद स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों/परियोजना डेवलपर्स को हरियाणा बिजली खरीद केन्द्र के साथ बिजली बेचने के लिए बिजली खरीद करार करना होगा।

3.4.3 स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों/परियोजना डेवलपर्स व हरियाणा बिजली खरीद केन्द्र एल.ओ.आई. जारी होने के तीन महीने के अन्दर बिजली खरीद करार करेंगे। इस अवधि के अतिरिक्त कोई झगड़ा होने पर कोई भी पार्टी सचिव, अक्षय ऊर्जा विभाग या उसके द्वारा नियुक्त किसी को भी निर्णय के लिए पहुंच कर सकती है।

3.4.4 इस नीति के तहत सभी सांविधिक मंजूरीयां और अनुमोदन एकल खिड़की सुविधा के माध्यम से समयबद्ध तरीके से 60 दिन की अवधि के भीतर आवश्यक आवेदन, जरूरी संलग्नों के साथ, फीस/चार्जिज एल.ओ.आई. सहित जमा करने के बाद स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को प्रदान किया जायेगा। संबंधित विभाग एकल खिड़की प्राधिकरण को 45 दिनों के अन्दर मंजूरी देगा।

इसके लिए अक्षय ऊर्जा विभाग/हरेडा अन्य संबंधित विभागों के साथ हरियाणा सरकार की ओर से एकल खिड़की प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा। निदेशक, अक्षय ऊर्जा विभाग/हरेडा एकल खिड़की सेवा के लिए प्राधिकरण होगा जबकि सचिव, हरियाणा सरकार अक्षय ऊर्जा विभाग अपीलीय प्राधिकरण होगा।

अक्षय ऊर्जा विभाग/हरेडा चुने गये योग्य परियोजना डेवलपर्स को भारतीय रिजर्व बैंक व भारत सरकार के दिशा निर्देशों अनुसार बैंकों से ऋण लेने के लिए सारी जरूरी सहायता उपलब्ध करवायेगा।

3-5 आवेदन शुल्क

छत के ऊपर ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र कैप्टिव उपयोग के लिए नेट मिटरिंग नियमों के तहत कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं होगा।

3-6 विकेन्द्रीकृत और ऑफ ग्रिड सौर आवेदन

राज्य विकेन्द्रीकृत और ऑफ ग्रिड सौर आवेदन जिसमें हाईब्रिड संयंत्र भी शामिल हैं को एम.एन.आर.ई./भारत सरकार के दिशा-निर्देशों अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान करके घरेलू और वाणिज्यिक उपयोग के लिए विभिन्न विद्युत और थर्मल ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रोत्साहन देगा।

गांवों/ढाणियों की बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए राज्य स्थानीय सौर ग्रिड की स्थापना, स्टैंडएलोन संयंत्र जैसे कि सोलर इन्वर्टर, सौर घरेलू प्रकाश संयंत्र, सौर पथ प्रकाश संयंत्र इत्यादि की स्थापना को प्रोत्साहन देगा।

आवासीय, औद्योगिक/वाणिज्यिक और सामाजिक क्षेत्र में गर्म पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए सौर जल तापन प्रणालियों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

आवासीय संस्थानों/औद्योगिक मैसों/होटल/बैरकस/मध्याह्न भोजन कार्यक्रम/हस्पतालों, कपड़ा/खाद्य उद्योग जहां औद्योगिक उपयोग के लिये भाप की जरूरत, समुदायिक खाना बनाने की जरूरतों इत्यादि को पूरा करने के लिए अक्षय ऊर्जा विभाग/हरेडा सौर भाप प्रणाली के उपयोग को बढ़ावा देगा।

अध्याय -4**अनुलाभ**

निम्नलिखित प्रोत्साहन/लाभ अवश्य स्थिति और परिचालन परियोजनाओं को चलाने के लिए सौर ऊर्जा परियोजनाओं को प्रदान किये जायेंगे:-

4-1 बिजली निकासी की सुविधा

सभी खर्च, अक्षय ऊर्जा टैरिफ और अन्य मुद्दों पर समय-समय पर संशोधित बिजली निकासी, पारेषण, वितरण लाइन और सिंक्रोनाइजिंग उपकरणों की स्थापना के लिए हरियाणा विद्युत नियामक आयोग के आदेशानुसार होंगे।

राज्य पारेषण उपयोगिता या पारेषण/वितरण लाइसेंसधारी अतिरिक्त उच्च वोल्टेज/उच्च वोल्ट 10 किलोमीटर अंतर संबंध बिन्दु की दूरी तक संचरण लाइन की लागत वहन करेगा। यदि इंटर कनेक्शन बिन्दु और ग्रिड कनेक्टिविटी बिन्दु के बीच की दूरी 10 किलोमीटर से अधिक है तो 10 किलोमीटर की दूरी से परे दूरी के लिए ट्रांसमिशन लाइन की लागत स्वतंत्र बिजली उत्पादक और लाइसेंसधारी के बीच समान रूप से वहन की जायेगी। हालांकि नहर आधारित सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पारेषण लाइनों उपयोगिताओं की लागत से मुक्त करके सबस्टेशन से परियोजना की दूरी की परवाह किये बगैर प्रदान किया जायेगा। पारेषण/वितरण लाइसेंसधारी की ग्रिड प्रणाली में एक दूसरे का संबंध बिंदु के बाद किसी भी आवश्यक वृद्धि की लागत भी चितित पारेषण/वितरण लाइसेंसधारी द्वारा वहन किया जायेगा।

4-2 बिजली कम्पनियों पीढ़ी आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर सबस्टेशन सहित ट्रांसफार्मर /निकासी की सुविधा की क्षमता को बढ़ायेगी।

4-3 विद्युत शुल्क एवं विद्युत कर और उपकर, व्हीलिंग, पारेषण और वितरण, क्रॉस सब्सीडी शुल्क, अधिभार और प्रतिक्रियाशील शक्ति प्रभार में छूट

भूमि व छत पर लगने वाले सौर ऊर्जा परियोजनाओं को विद्युत शुल्क एवं विद्युत कर और उपकर, व्हीलिंग, पारेषण और वितरण, क्रॉस सब्सीडी शुल्क, अधिभार और प्रतिक्रियाशील शक्ति प्रभार में पूर्ण रूप से छूट दी जायेगी।

4-4 उद्योग का दर्जा

मेगावाट पैमाने पर सौर ऊर्जा पैदा करने की सभी नई परियोजनाओं को राज्य की औद्योगिक नीति के तहत उद्योग का दर्जा दिया जायेगा। इस तरह सभी प्रोत्साहन जोकि समय-समय पर औद्योगिक नीति के तहत औद्योगिक इकाइयों के लिए उपलब्ध हैं यह भी सौर ऊर्जा उत्पादकों/इकाइयों के लिये उपलब्ध होगा।

4-5 मूल्य वरीयता

जो स्वतंत्र विद्युत उत्पादक राज्य में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करेगा उसको मूल्य वरीयता दी जायेगी।

4-6 बैंकिंग

हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड/दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड/उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड/लाइसेंसधारी पात्र उत्पादकों द्वारा पैदा की गई सौर ऊर्जा को बैंकिंग की अनुमति देगा। लाइसेंसधारी/बिजली कंपनियों द्वारा बैंकिंग की सुविधा एक वर्ष के लिए दी जाएगी तथा स्वतंत्र विद्युत उत्पादक को बिजली देते समय व लेते समय के अनशेंडयूल्ड इंटरचेंज शुल्क (यूआई शुल्क) के अंतर का भुगतान करना होगा। तथापि बैंक की भी बिजली का आहरण पीक तथा टाइम ओफ डे (टीओडे) अवधि में अनुमन्य नहीं होगा। यदि संबंधित बिजली कंपनियों/लाइसेंसधारियों के पास जमा की गई बिजली को बारह महीने की अवधि में उपयोग नहीं किया गया तो यह स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा इसके एवज में शुल्क देय नहीं होगा।

- बैंकिंग सुविधा मेगावाट पैमाने पर परियोजनाओं के अनुसार ग्रिड से जुड़े छत सौर बिजली परियोजनाओं के लिए प्रदान की जायेगी ।
- 4-7 **अक्षय ऊर्जा प्रमाण पत्र**
सौर ऊर्जा संयंत्र से बिजली के उत्पादन में लगी कम्पनी, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के विनियमों के अनुसार अक्षय ऊर्जा प्रमाण पत्र के पात्र होंगे ।
- 4-8 **भूमि उपयोग मंजूरी, बाहरी विकास शुल्क, जांच शुल्क तथा बुनियादी ढांचा शुल्क में छूट**
राज्य में मेगावाट स्तर के सौर ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा भूमि रूपांतरण मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। यह परियोजनाएं बाहरी विकास शुल्क, जांच शुल्क तथा बुनियादी ढांचा शुल्क से मुक्त होगी परन्तु यदि कोई विशेष सेवा सौर परियोजनाओं के लिए आवश्यक है तो बाहरी विकास शुल्क यथानुपात आधार पर लिया जायेगा । इस तरह की परियोजनाओं का ब्योरा नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग को सूचित किया जायेगा ।
तथापि, खरीद शक्ति समझौते की अवधि समाप्त होने के बाद या संयंत्र बंद होने के उपरांत, क्षेत्र/शहर/कस्बे के मास्टर प्लान के अनुसार भूमि मूल रूप में लौट जायेगी (यह भूमि अपने मूल स्थिति में बदल जायेगी)।
- 4-9 **पर्यावरण क्लिरेंस में छूट**
इन परियोजनाओं को हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी ।
- 4-10 **वन विभाग की मंजूरी में छूट**
जहां कहीं भी स्पष्ट रूप से निषिद्ध नहीं है और जहां भी संभव है, अगर उनकी अधिनियम/अधिसूचना के तहत वन विभाग, हरियाणा से मंजूरी आवश्यक है तो अक्षय ऊर्जा विभाग की एकल खिड़की मंजूरी के अधिकार एजेंसी द्वारा सुविधा होगी ।
- 4-11 **परियोजनाओं के लिए भूमि की लीज के लिए स्टाम्प ड्यूटी में छूट**
मेगावाट पैमाने की इन परियोजनाओं की स्थापना के लिए ली जाने वाली भूमि किराये पर/लीज डीड के पंजीकरण के लिए शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान में 100 प्रतिशत छूट दी जायेगी।
- 4-12 **अप्रयुक्त जगह का उपयोग**
धरातल आधारित मेगावाट स्तर पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना में बीच की खाली जगह का उपयोग वाणिज्यिक फूलों की खेती/बागवानी से संबंधित कार्य के लिए उपयोग कर सकते हैं बशर्ते कि यह सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रभावित नहीं करेगा और सभी सुरक्षा और सुरक्षा के उपाय, विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार स्थापित उपकरणों के लिए जरूरी होंगे।
- 4-13 **पैमाइश**
बिजली उत्पादन एवं इसकी बिक्री के लिए पैमाइश उपकरणों, राज्य बिजली कम्पनियों/ एच.आर.सी. ग्रिड कोड/ सी.ई.ए. मानकों (स्थापना और मीटर के ऑपरेशन) विनियम, 2006 और तत्पश्चात संशोधन के विनिर्देश अपने स्वयं के खर्च पर इकाई द्वारा स्थल पर स्थापित किया जायेगा ।
इन उपकरणों का परीक्षण, बिजली कम्पनियों द्वारा उपयोगकर्ता के खर्चे पर किया जायेगा । बिजली कम्पनियां ऐसे स्थानों पर जहां एक से अधिक परियोजना स्थापित की जायेगी वहां बुनियादी ढांचे का विकास करेगी ।
पैमाइश और संबंधित उपकरण निम्नलिखित तरीकों से स्थापित किये जायेंगे:-
क. एक दूसरे का संबंध बिंदु पर मुख्य मीटर स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों द्वारा प्रदान किया जायेगा ।
ख. एक दूसरे का संबंध बिंदु पर जांच मीटर निगम/डिस्काम द्वारा प्रदान किया जायेगा ।
ग. निगम के सब-स्टेशन पर मुख्य मीटर निगम/डिस्काम द्वारा प्रदान किया जायेगा ।
घ. निगम के सब-स्टेशन पर जांच मीटर कम्पनी द्वारा प्रदान किया जायेगा ।
उत्पादित बिजली की पैमाइश निगम/डिस्काम के सब-स्टेशन पर की जायेगी ।
- 4-14 **विद्युत क्रय करार का कार्यकाल**
विद्युत क्रय करार जोकि स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों और हरियाणा बिजली खरीद केन्द्र के बीच होगा वह 25 वर्षों के लिए वैध होगा । इस अवधि के बाद बिजली खरीद समझौते पर बिजली उत्पादकों और संबंधित बिजली कम्पनियों/लाईसैंसधारियों के बीच फिर से बातचीत हो सकती है।
- 4-15 **ब्याना जमा (ई.एम.डी.)**
ग्रिड से जुड़े सौर विद्युत परियोजनाओं के लिए आवेदन के साथ 2 लाख रुपये प्रति मेगावाट (200 रुपये प्रति किलोवाट) डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करानी होगी जोकि समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर होने के बाद वापिस की जायेगी । तथापि यदि निविदादाता/डेवलपर सुरक्षा राशि जमा करने में असफल रहता है/इंकार करता है अथवा

नियत समय में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने में असफल रहता है/इंकार करता है तो निविदादाता की ब्याना राशि जब्त कर ली जायेगी।

4-16 प्रवर्तक की न्यूनतम इक्विटी

परियोजना डेवलपर व्यक्ति/कम्पनी/फर्म/कम्पनियों के समूह या एक संयुक्त उद्यम/4 से ज्यादा भागीदारों के कंसोर्टियम जिनका प्रमुख भागीदारी में कम से कम 51 प्रतिशत हो, हो सकता हो।

ग्रिड से जुड़े सौर परियोजना डेवलपर प्रमोटरों और कंपनी में अपनी हिस्सेदारी के बारे में, बोली दस्तावेज और प्रमुख शेयरधारकों का संकेत करते हुए जानकारी प्रदान करेगा। आवेदन जमा करने की तिथि और परियोजना के निष्पादन से एक साल तक सौर ऊर्जा परियोजना के विकास में प्रमुख शेयरधारक में किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी। यह पब्लिक लिमिटेड कम्पनी द्वारा विकसित किये जाने वाले सौर विद्युत परियोजनाओं पर लागू नहीं होगी। इसके बाद, कोई भी बदलाव केवल अक्षय ऊर्जा विभाग/हरेडा या हरियाणा बिजली खरीद केन्द्र को सूचना देकर, जैसा भी मामला हो, किया जा सकता है।

इसके अलावा इस नीति के तहत केवल नए संयंत्र और मशीनरी को अनुमति दी जायेगी।

अध्याय-5

पहल

छत सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

5-1 सौर ऊर्जा संयंत्रों की अनिवार्य स्थापना

हरियाणा सरकार द्वारा 500 वर्ग गज या उससे ज्यादा के आवासीय भवनों, सभी सरकारी व प्राइवेट शिक्षण संस्थानों, स्कूलों, कालेजों, हास्टलों, तकनीकी/व्यवसायिक शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, 30 किलोवाट व अधिक स्वीकृत क्षमता से ज्यादा के कार्यालयों, सभी 50 किलोवाट व अधिक क्षमता के निजी हस्पतालों, नर्सिंग होमस, औद्योगिक स्थापनाओं, वाणिज्यिक स्थापनाओं, मॉलस, होटल, मोटल, बैंकटहाल, पर्यटन स्थलों, ग्रुप हाउसिंग समितियों, भवन निर्माता, हाउसिंग बोर्ड द्वारा आधा एकड़ या उससे अधिक के प्लॉट पर विकसित किये जाने वाले सभी नये आवासीय स्थलों तथा सिंचाई विभाग के सभी पम्प हाउसों पर सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 3.9.2014 द्वारा स्वीकृत क्षमता का 3 से 5 प्रतिशत क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना बाध्य किया गया है।

आवासीय क्षेत्र में, इसकी अनिवार्य स्थापना केवल नये आवासीय भवनों के लिए होगी जबकि मौजूदा आवासीय भवनों में छत पर लगाने वाले सौर ऊर्जा संयंत्रों को वित्तीय प्रोत्साहन देकर प्रोत्साहित किया जायेगा। अन्य क्षेत्रों के लिए मौजूदा इमारतों को भी शामिल किया जायेगा।

यदि उपयोगकर्ता अनिवार्य प्रावधान की अधिसूचना के तहत छत आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित नहीं करता तो सरकारी नियमों व अधिनियमों के तहत उस पर दंड लगाया जायेगा।

5-2 शुद्ध पैमाइश सुविधा

मंजूर लोड की क्षमता के बराबर ग्रिड से जुड़े छत सौर फोटोवोल्टिक प्रणालियां कैप्टिव इस्तेमाल के लिए स्थापित की जा सकती है जिसके लिए शुद्ध पैमाइश सुविधा हरियाणा बिजली विनियामक आयोग द्वारा प्रदान की जायेगी। इस तरह की व्यवस्था से उत्पन्न बिजली वित्तीय वर्ष के दौरान संचयी बिजली की खपत का 90 प्रतिशत पर समायोजित किया जायेगा। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान 25 पैसे प्रति यूनिट का प्रोत्साहन सौर ऊर्जा द्वारा उत्पन्न बिजली बिलों में दिया जायेगा। इन विनियमों के तहत दिये जाने वाले प्रोत्साहनों, साल के आगमन/टैरिफ याचिका उस साल के लिए और तदनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 और उसके बाद दिये जाने वाले प्रोत्साहनों की हर साल आयोग द्वारा समीक्षा की जायेगी।

इस संदर्भ में, हरियाणा बिजली विनियामक आयोग द्वारा समय-समय पर जारी संशोधनों का अनुपालन किया जायेगा।

5-3 सरकारी भवनों/भूमि का लीज

सरकारी संगठनों, संस्थाओं, भवनों व खाली भूमि की छत पर उपलब्ध जगह को पट्टा/किराये पर स्वतंत्र बिजली उत्पादकों/रैस्को डेवलपर को सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए दिया जायेगा।

ऐसी साइटों के लिए पट्टा/किराया दर संबंधित जिले के उपायुक्त, पी.डब्ल्यू.डी. (बी एंड आर.) विभाग व जिस विभाग का भवन है, की समिति द्वारा निर्धारित की जायेगी। डेवलपर इस बिजली की आपूर्ति उस भवन के कैप्टिव इस्तेमाल के लिए जहां संयंत्र शुद्ध पैमाइश के साथ स्थापित किया गया है, कर सकता है और बाकी बिजली हरियाणा बिजली खरीद केन्द्र को अन्तिम न्यूनतम निर्धारित खरीद पर उनको बेच सकता है तथा तीसरी पार्टी को भी हरियाणा बिजली विनियामक आयोग अधिनियम के तहत बेच सकता है।

5-4 कृषि सौर पम्प सैट्स

पानी/सिंचाई की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य केन्द्रीय सरकार/नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से सौर आधारित पम्प सैटों की स्थापना को अनुदान समर्थन द्वारा प्रोत्साहित

करेगा। सौर पम्प सैटो से अतिरिक्त बिजली उत्पादन को हरियाणा बिजली खरीद केन्द्र औसत बिजली दर से खरीद सकता है। इस तरह उत्पादित सौर ऊर्जा डिस्काम की आर.पी.ओ. को पूरा करने में भी गिनी जायेगी।

अध्याय-6

दिशा निर्देश

6-1 तकनीकी जरूरतें

ग्रिड से बंधे/जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों से बिजली उत्पन्न करने वाले स्वतंत्र बिजली उत्पादकों व उपयोगकर्ताओं को तथा आफ ग्रिड सौर उपकरणों के उपयोगकर्ताओं को नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट विनिर्देशों का राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय मानकों का या समय-समय पर संशोधित, और प्रासंगिक आई.ई.सी./बी.आई.एस. के मानकों या लागू मानकों को जैसा कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट जैसा भी मामला हो, का कड़ाई से पालन करना होगा।

स्वतंत्र बिजली उत्पादकों को हरियाणा बिजली विनियामक आयोग अक्षय ऊर्जा अधिनियम, 2010, समय-समय पर संशोधित, का पालन करना होगा।

6-2 नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय, भारत सरकार की अन्य योजनाएं

सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना को नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय, भारत सरकार की जवाहर लाल नेहरू सोलर मिशन के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों जैसे कि वायबिल्टी गैप फंडिंग, बेरोजगार युवकों/किसानों की परियोजना, राष्ट्रीय विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड का बंडलिंग कार्यक्रम/राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम(एन.टी.पी.सी.) और छत सौर ऊर्जा संयंत्रों के कार्यक्रम की योजना उनके दिशा निर्देशों के अनुसार, समय-समय पर प्रोत्साहन दिया जायेगा।

6-3 नोडल एजेंसी

हरियाणा सरकार की ओर से अक्षय ऊर्जा विभाग, हरियाणा सौर ऊर्जा नीति-2016 को क्रियान्वित करने के लिए नोडल एजेंसी होगा।

सभी परियोजना डेवलपर उत्पन्न ऊर्जा, अर्जित राजस्व, बिजली का पहलू और प्लांट लोड फैक्टर के तथा प्लांट लोड पेरामीटर तथा पूरी उपलब्धि के कारणों व अन्य कोई सूचना जैसा कि अक्षय ऊर्जा विभाग/हरेडा चाहेगा के संबंध में मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ताकि राज्य में सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली का डाटा बैंक स्थापित/अपडेट हो सके और साथ ही आर.पी.ओ. अधिनियमों के तहत उसकी निगरानी कर सके।

6-4 संशोधन/छूट/नीति के प्रावधानों की व्याख्या

सचिव, अक्षय ऊर्जा विभाग, हरियाणा सरकार इस नीति के तहत किसी भी मुद्दे के प्रावधानों की व्याख्या से संबंधित सरकारी विभाग/एजेंसियों से परामर्श करके संशोधन करने/छूट देने/स्पष्टीकरण जारी करने के लिए सक्षम होगा।

अध्याय-7

परिभाषाएं

7-1 नीति में इस्तेमाल वाक्यरीति को परिभाषित किया गया है -

- (1) अधिनियम का मतलब विद्युत अधिनियम, 2003 व इसमें संशोधन सहित।
- (2) एपीपीसी का मतलब औसत बिजली खरीद लागत है।
- (3) नहर का मतलब फीडर, नहर, रजबाहा, माईनर, ड्रेन चैनल व लघु सिंचाई नलकूल निगम के नाला।
- (4) सीईए का मतलब केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण है।
- (5) सीईआरसी का मतलब भारत की केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग जिसका गठन विद्युत अधिनियम, 2003, या उसके उत्तराधिकारियों की धारा 76 की उपधारा (1) के अधीन किया गया है।
- (6) केंद्रीय एजेंसी का मतलब नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर (एनएलडीसी) जो कि आरईसी विनियम के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के आदेश दिनांक 29.1.2010 द्वारा नामित है।
- (7) पारंपरिक ऊर्जा संयंत्रों का मतलब लिग्नाइट कोयला, जीवाश्म ईंधन या गैस आधारित थर्मल स्टेशन और अधिक से अधिक 25 मेगावाट क्षमता की जलविद्युत उत्पादक स्टेशन।
- (8) हरियाणा डीस्कॉम का मतलब वितरण लाइसेंसधारी जैसे कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, पंचकूला, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, हिसार।
- (9) फडीपीआर का मतलब संभव विस्तृत परियोजना रिपोर्ट।
- (10) सरकार और राज्य का मतलब क्रमशः हरियाणा सरकार और हरियाणा राज्य है।
- (11) इरेडा का मतलब भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी है।

- (12) लाइसेंसधारी का मतलब एक व्यक्ति जो अधिनियम की धारा 14 के तहत एक लाइसेंसधारी है ।
- (13) एमएनआरई का मतलब नया और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, विकास और देश की अनुपूरक ऊर्जा आवश्यकता के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा की तैनाती के लिए जिम्मेदार केन्द्रीय सरकार का मंत्रालय है ।
- (14) एमओयू का मतलब समझौता ज्ञापन है ।
- (15) राष्ट्रीय सौर मिशन या सौर मिशन का मतलब भारत सरकार द्वारा शुरू की जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन 2009 है ।
- (16) एन.टी.पी.सी. का मतलब नैशनल थर्मल पावर कारपोरेशन ।
- (17) एन.वी.वी.एन.एल. का मतलब राष्ट्रीय विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड ।
- (18) नोडल एजेंसी का मतलब हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (हरेडा) या अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा नामित किसी अन्य एजेंसी है.
- (19) पीपीए का मतलब बिजली खरीद समझौते है ।
- (20) आरईसी विनियमन या सीईआरसी आरईसी विनियमन का अर्थ केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (अक्षय ऊर्जा उत्पादन पर नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए व मान्यता के लिए नियम व शर्त) विनियमन, सीईआरसी केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित नियमन, 2010 दिनांक 14.01.2014 और समय समय पर उसका संशोधन । .
- (21) अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्र या आरईसी का अर्थ केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (अक्षय ऊर्जा उत्पादन पर नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए व मान्यता के लिए नियम व शर्त) विनियमन, 2010 की शर्तों पर केंद्रीय एजेंसी द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा (सौर) प्रमाणपत्र ।
- (22) एचइआरसी / आयोग का मतलब हरियाणा विद्युत नियामक आयोग है ।
- (23) आरपीओ का मतलब अक्षय खरीद बाध्यता है ।
- (24) एसईसीआई का मतलब भारत का सौर ऊर्जा निगम है ।
- (25) सौर बिजली उत्पादक का मतलब वह इकाई जो बिजली उत्पन्न करने के लिए सुविधाओं का मालिक है और हरियाणा की बिजली वितरण लाइसेंसधारी को बिक्री के लिए एनवीवीएन/तीसरे पक्ष को बिक्री के लिए/कैप्टिव उपयोग के लिए बिजली उत्पन्न करता है ।
- (26) सौर संयंत्र/सौर ऊर्जा संयंत्र का मतलब बिजली संयंत्र या प्रणाली है जो सौर फोटो वोल्टेक या केंद्रित सौर तापीय उपकरणों पारंपरिक जीवाश्म ईंधन में एकीकरण सहित के माध्यम से सौर ऊर्जा का उपयोग करके एक बिजली का उत्पादन करता है ।
- (27) सौर पीवी बिजली संयंत्र का मतलब है सोलर फोटो वोल्टीक (एसपीवी) प्लांट है जो सूरज की रोशनी का उपयोग करता है और इसे फोटोवोल्टीक प्रौद्योगिकी के माध्यम से बिजली में प्रत्यक्ष रूपांतरण करता है ।
- (28) शुल्क (टेरिफ) का मतलब शुल्को की अनुसूची जिसमें उत्पादन, पारेषण, व्हीलिंग और बिजली की आपूर्ति और उसका प्रयोग नियम और शर्तें ।
- (29) टीओडी का मतलब दिन का समय घंटे में ।
- (30) यूआई चार्ज का मतलब अनिर्धारित इंटरचेंज शुल्क है ।
- (31) ई.एच.वी. का मतलब अतिरिक्त उच्च वोल्टेज ।
- (32) एच.वी. का मतलब उच्च वोल्टेज ।
- (33) एम.डब्ल्यू. का मतलब मेगावाट ।
- (34) के.डब्ल्यू.पी. का मतलब किलोवाट पीक ।
- (35) एल.ओ.आई. का मतलब आशय पत्र ।
- (36) एच.पी.पी.सी. का मतलब हरियाणा बिजली खरीद केन्द्र ।

7.2

अन्य सभी शब्द और भाव जिनका यहां प्रयोग किया गया है लेकिन उनका अर्थ परिभाषित नहीं है उनकी परिभाषा के विद्युत अधिनियम -2003 के अनुसार परिभाषित होगी ।

अंकुर गुप्ता,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अक्षय ऊर्जा विभाग, चण्डीगढ़ ।

HARYANA GOVERNMENT
RENEWABLE ENERGY DEPARTMENT

Notificaiton

The 14th March, 2016

No. 19/4/2016-5 Power.-The Government of Haryana has formulated Haryana Solar Power Policy, 2016 to promote the generation of power from solar energy. For giving effect to this Policy, necessary amendments in various policies, rules and regulations, wherever necessary, shall be expeditiously undertaken by the concerned Department.

HARYANA SOLAR POWER POLICY, 2016

CHAPTER-I

INTRODUCTION

1.1 Why Solar Energy?

To begin with, we need to survive. Live. If choice be, live well in a sustainable manner. Solar Energy has come to be accepted as a major source of energy for the future. Specifically in India, it is expected that coal reserves of the country won't last longer than 2040-50. Oil reserves across the world are also depleting and have their own pollution factors associated with it.

Meanwhile, *Solar Energy*:

- Is sustainable and renewable
- Requires little maintenance
- Is environment friendly so there is avoidance of emission of green house gases and reduced carbon emissions
- Is a source of ongoing free energy-inexhaustible and the best replacement to other non renewable sources
- Helps in avoidance of the volatility of price
- Saves eco systems and livelihoods
- It can be used for a variety of purposes and fits in perfectly not only in the rural set up in India, but also for many items for the urban population
- It is inexpensive since solar panels can be placed easily and it is not always necessary to set up a power or gas grid
- Solar energy can become an important contributor to the electricity mix required

1.2 The Indian Scenario

India today heralds periods of economic growth, increasing prosperity, a growing rate of urbanisation and rising per capita energy consumption which has all widened the access to energy in the country. The country is riding high on the objective of developing solar technologies and ensuring inclusive solar power development throughout.

In particular,

- It is targeted that there would be about 1, 00,000 MW of solar power generated in India by 2022.
- India's annual solar installations would go up four times by 2017
- Government of India has set targets which will take the total renewable capacity to almost 175 GW by the end of 2022
- This includes 60 GW from wind power, 100 GW from solar power, 10 GW from biomass power and 5 GW from small hydro power

1.3 Haryana – the Competitive Advantage

The State of Haryana is located in the northern part of India, populated by about 25.35 million people and covers an area of about 44212 sq kilometres. In terms of food production, per capita income, industrial growth, excellent transport and communication facilities the State easily qualifies as one of the most advanced states of the country. It has

- a fast growing economy
- world class infrastructure
- access to a huge market in the NCR
- investor friendly policies

- harmonious labour relations
- strategic locations
- rail, road and air connectivity
- skilled manpower
- rapid urbanization and industrialization
- law and order

1.4 A Vision for Power – the Mission therein

In an environment where the demand for energy and power is growing rapidly the State seeks to build on renewable energy and be a part of the drive that is taking a firm shape in the entire country.

The State is blessed with high solar radiation levels with more than 300days of clear sunlight and seeks to harness the untapped and inexhaustible solar energy potential in the State.

The State therefore seeks to:

- Promote generation of green and clean power
- Create conditions that would be conducive to the participation of the private as well as public sector in the setting up of solar energy projects in the country
- To encourage and promote a feasible Investment environment for the same
- Spread environmental consciousness among all citizens of the State
- Aim for a decentralized and diversified management of the energy sector
- To work consistently towards an increase of the share of the renewable solar power
- To attain its target of Soar Renewable Purchase Obligation (Solar RPO) which is just 0.25% at present and would be scaled up to at least 8% by 2021-22
- To ultimately create a technology driven State with the right 'energy mix'

1.5 Title and Implementation :

- 1.5.1 This policy will supersede the **Haryana Solar Power Policy, 2014.**
- 1.5.2 This policy will be known as **Haryana Solar Power Policy, 2016.**
- 1.5.3 The policy will come into operation with effect from the date of its notification and will remain in force till a new Policy is notified. .
- 1.5.4 The State Government may undertake review of this policy as and when the need arises in view of any technological breakthrough or to remove any inconsistency with Electricity Act, Rules & Regulation made thereof or any Government of India policy/State Electricity Regulatory Commission's order.

1.6 Objectives:

The objectives of this policy are to:

- 1.6.1 To promote generation of green and clean power in the State using solar energy.
- 1.6.2 To create conditions conducive to the participation of private and public sector as well as PPP in the promotion and setting up of up Solar Energy based power projects in the State.
- 1.6.3 Productive use of wastelands / non – agricultural lands thereby leading to socio-economic transformation and a reduction in regional disparities in development.
- 1.6.4 Employment generation and skill up gradation of the youth.
- 1.6.5 To put in place an appropriate investment climate that would leverage the benefits of Clean Development Mechanism (CDM) and result in lower Green House Gas (GHG) emissions.
- 1.6.6 Co-creation of Solar Centres of Excellence and pools of technical professionals which would work towards applied research and commercialization of indigenous and cutting edge technologies involving applications of solar energy generation and appliances.
- 1.6.7 Spreading of environmental consciousness among all citizens of the State especially the youth and school going children.
- 1.6.8 Decentralization and diversification of the energy portfolio and to increase the share of renewable solar power.

1.7 Solar Renewable Energy Purchase Obligation (RPO):

The Regulatory Commission of Haryana so far has prescribed the Solar RPO of 3% by the year 2021-22.

The Ministry of New & Renewable Energy, Govt. of India is planning to scale up the ambitious target to add 1, 00,000 MW of solar power by 2022. To achieve this target, the Ministry is planning to raise the solar renewable purchase obligation (RPO) targets for obligated entities (including distribution companies) to 8% from the current level of 3%. For Haryana State, this will translate to installed capacity of 3200 MW solar power by the year 2021-22.

To achieve the solar RPO, following initiatives shall be taken by the Govt.:-

- (a) Installation of ground mounted MW scale solar power plants.
- (b) Installation of solar power plants by the Haryana Power Generation Corporations on its land.
- (c) Development of solar parks through Saur Urja Nigam Haryana Ltd. (SUN Haryana).
- (d) Installation of solar power plants under schemes of Ministry of New & Renewable Energy like VGF scheme, unemployed youth/farmers scheme and purchase of power under bundling scheme of National Vidyut Vyapar Nigam Ltd. (NVVNL)/NTPC.
- (e) Installation of solar power plants on canal banks.
- (f) Rooftop grid connected solar power plants through net metering.
- (g) Rooftop grid connected solar power plants on cluster of Govt. /PSU buildings.

- 1.8 The regulators i.e CERC/HERC will recognize the entire cost incurred toward the purchase of solar power in the ARR order issued from time to time.

CHAPTER-II GROUND MOUNTED POWER PROJECTS

2.1 Ground mounted megawatt scale power plants:

Solar power projects shall be set up by the independent power producers (IPP) for which Haryana Power Purchase Centre (HPPC) shall invite bids through open competitive bidding tenders. The Independent Power producers shall meet with all the requirements, as per the State Grid Code, for setting up their projects.

For connectivity with grid, the IPPs shall connect the Solar Power Plant with the nearest Sub-Station of Transmission/Distribution Licensee and inject the electricity at appropriate voltage of the Sub-station.

2.2 Capacity reservation

The HPPC will float the tenders from time to time for inviting bids for purchase of solar power. Each bid shall be comprised of the power required to be purchased for fulfilling the RPO plus 20% additional power for allocation to the small generators of 1MW to 2 MW capacity.

- 2.3 HPPC will purchase solar power over and above the RPO obligation subject to a limit of 200 MW.

- 2.4 A price preference of 2% will be given to the solar power generators of 1MW to 2 MW capacity who set up their plants within the territory of Haryana State as compared with the solar power plants who supply power from the plants located out side the territory of Haryana.

2.5 Development of Solar Parks

To bring significant investment from project developers, to meet the Solar Renewable Purchase Obligation (RPO) mandate, to achieve the targets fixed by the Government and to boost the economy Solar Parks will be set up in the State. For that a Joint Venture company has been formed by HSIIDC and HPGCL named "Saur Urja Nigam Haryana Limited" (SUN Haryana). This company will aggregate lands in various parts of the State for setting up Solar Parks/Solar Power Plants through Private Power Producers.

2.6 Solar Power Projects set up on Canal tops/banks:

The setting up of MW scale Solar Power Plants on canals tops/banks shall be encouraged as per the guidelines and incentives issued by MNRE, Government of India, from time to time. For that the sites for shadow free space available on canal banks shall be indentified in consultation with Irrigation Department, Haryana. The bidder shall be selected through open competitive bidding by a separate tender by HPPC. The entire power from the Solar Power Plant shall be purchased by HPPC, if need be, to meet their RPO, at the

tariff so discovered. They shall be provided with all the benefits as provided for Ground Mounted Megawatt scale Power Projects including free evacuation facility irrespective of the distance by the State. Further the Independent Power Producers, who have already set up small hydro projects on the canals, shall also be motivated to set up solar power projects on the canal tops/banks allocated to them.

2.7 Panchayat Land on Lease /Rent basis

The Government of Haryana will facilitate the lease/sub-lease of Panchayat land at reasonable rates through SUN Haryana (Saur Urja Nigam Haryana) or directly through Panchayat (as per prevailing Govt. Policy) for setting up of Solar Power Projects for minimum period of 30 years.

2.8 MW scale ground mounted Grid Connected Solar Power Projects (Procedure)

2.8.1 For setting up of MW scale solar power project in the State, Haryana Power Purchase Centre (HPPC) shall invite the bids through open competitive bidding process and issue LOI to the project developer(s)/power producer(s), on the basis of evaluation parameters contained in the tender document. The HPPC will communicate the rates of the purchase to the Renewable Energy Department/HAREDA from time to time after the finalization of every tender.

After issue of letter of intent (LOI) the project developer(s)/power producer(s) shall submit the proposal to HPPC for all clearances. After issue of clearances, HPPC will sign PPA with the IPPs/ project developer(s).

2.8.2 The Solar power projects will be out of the preview of the Land Ceiling Act of the government.

CHAPTER-III ROOFTOP POWER PROJECTS

3.1 Rooftop Grid connected / off-grid solar power projects.

There is a great potential to generate solar power through installation of rooftop solar power plants in the State. Accordingly the installation of 1kWp to 1 MWp of capacity Grid connected & up to 50 kWp of capacity off-grid Solar roof-top Power Plants on the rooftops of Industries, Public and Private Institutes, Schools, Colleges, Commercial& Social Institutions/Establishments, Charitable Trust Bhawans, Hospitals and Residential Buildings etc. shall be promoted for their captive use/net meter as per the State Government Regulation.

For installation of rooftop solar power plants the State Government shall provide capital /generation subsidy/ incentives.

A total capacity of 1600 MW rooftop solar power plants shall be added by the year 2021-22.

3.2 Cluster of rooftops of public / private buildings

Some percentage capacity (to be fixed from time to time) of the setting up of ground mounted mega watt scale grid connected power plants, to meet the solar RPO shall be developed by setting up of grid connected rooftop solar power plants. For that the offers shall be invited by Renewable Energy Department, Haryana/HAREDA from the independent power producers for development of grid connected rooftop solar power plants, of capacity ranging from 250 kWp to 1 MW, on a cluster of public private buildings on the last lowest tariff discovered and conveyed by HPPC. The entire power produced by power producers who set up plants within four years from the date of notification of this policy shall be purchased by the HPPC or any entity of Haryana Govt. Alternatively, the developer can also supply/provide the power for the captive use of the premises where the system is installed along with net meter and can sell the remaining power to HPPC or any entity of Haryana Government on the last lowest tariff discovered and conveyed by HPPC or to third party as per HERC regulations.

All maximum and extra benefits possible will be extended to Roof Top Solar Power Producers.

No permission is required from the building plan sanctioning authority for setting up of rooftop solar power plants. These Rooftop Solar Power Plants shall also be eligible for RPO/REC benefits.

3.3 Power Evacuation

For Rooftop grid connected SPV system, installed for captive use or sale of power to power utilities/third party sale through open access, all arrangements for power evacuation i.e. voltage step up, synchronizing

equipments, metering shall be done by the user as per the technical specifications, guidelines and regulation issued by HERC. However, if dedicated transmission line is required then it shall be as per procedure of ground mounted power plants.

3.4 Rooftop solar power projects (Procedure)

- 3.4.1 The programme for rooftop solar power projects (MW scale as well as small projects) including net metering programme shall be implemented by Renewable Energy Department.
- 3.4.2 Once the proposal has been approved (LOI issued), the IPPs/project developer(s) will be required to enter into PPA with HPPC for the sale of power to it.
- 3.4.3 In case of any dispute either party can approach Secretary, renewable Energy Department or any body appointed by him for a decision in the matter.
- 3.4.4 Wherever required under this policy, all the statutory clearances and approvals shall be provided to the IPP through a single window facility, in a time bound manner within a period of 60 days after the submission of complete application along with necessary enclosures, fees/charges including LOI. The concerned department will give the clearance to the single window authorities within 45 days.

For that, the Renewable Energy Department/ HAREDA along with the concerned Departments shall function as single window authority on behalf of Government of Haryana. The Director, Renewable Energy Department/HAREDA shall be the authority for the single window service while Secretary to Government Haryana, Renewable Energy Department, Haryana will be the Appellate Authority.

The Renewable Energy Department/HAREDA will provide all requisite help to selected eligible project developer for getting the loan sanctioned from the banks as per the guidelines of Reserve Bank of India and the Government of India.

3.5 Application fee

For Roof top grid connected solar power plant installed for captive use, under net-metering regulations, there shall be no processing fee.

3.6 Decentralized and Off Grid Solar Applications

The State will promote the installation of decentralized and off-grid solar applications, including hybrid systems, as per guidelines issued by MNRE, Government of India, to meet various electrical and thermal energy requirements for domestic and commercial use by providing financial assistance.

For that the State will promote setting up of local solar grid and stand-alone systems like solar inverter, solar home lighting systems, solar street lighting systems etc. to meet the lighting energy needs of villages/dhanis.

For meeting the hot water requirement in the residential, industrial, commercial and social sector the installation of solar water heating system shall be promoted.

To meet the Community cooking energy needs in residential institutions/industrial mess/Hotels/Barracks/ mid day meal program/Hospitals etc., Industrial Application of steam in process industries such as Textile/Food industry etc. ,Laundries & Process steam requirements in industries etc. the Department/ HAREDA shall promote the use of solar steam systems.

CHAPTER-IV

PERQUISITES

The following incentives/benefits shall be provided to the Solar Power Projects on 'Must Run Status and Operational Projects':

4.1 Power Evacuation Facility

All expenses for power evacuation, Transmission, distribution line and synchronizing equipment required for installation will be as per the orders of the Haryana Electricity Regulatory Commission for Electricity on Renewable energy Tariff & other issues, as modified from time to time.

The State transmission utility or the Transmission/Distribution Licensee shall bear the cost of Extra High Voltage (EHV)/ High Voltage (HV) transmission line up to a distance of 10 km. from the inter-connection point. In case the distance between the inter connection point and point of grid connectivity is more than 10

kms. then the cost of transmission line for the distance beyond the 10 kms. shall be borne equally between the Independent Power Producer and the licensee. However for canal based solar power projects, the transmission lines shall be provided by the utilities, free of cost, irrespective of the distance of the project from the substation. The cost of any augmentation required after the interconnection point in the grid system of the Transmission/Distribution Licensee shall also be borne by the concerned Transmission/Distribution Licensee.

- 4.2** Power utilities will keep on upgrading the capacity of transformer/evacuation facility including the substation from time to time as per the generation requirement.

4.3 Exemption of Electricity Duty & Electricity Taxes & Cess, Wheeling, Transmission & distribution, cross subsidy charges, surcharges and Reactive Power Charges:

All electricity taxes & cess, electricity duty, wheeling charges, cross subsidy charges, Transmission & distribution charges and surcharges will be totally waived off for Ground mounted and Roof Top Solar Power Projects.

4.4 Status of Industry

All new projects of MW scale generating solar energy will be treated as "Industry" in terms of Industrial Policy of the State. Thus all the incentives available to industrial units under the industrial policy from time to time, shall also be available to the solar power producers/units.

4.5 Price Preference

Price preference will be given to IPPs who set up the Solar Power Plants in the State.

4.6 Banking

Haryana Vidyut Parsaran Nigam Ltd. (HVPNL)/ Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam Ltd. (DHBVN)/ Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam Ltd. (UHBVN)/ licensee shall permit solar power generated by eligible producers to be banked. The banking facility shall be allowed for a period of one year by the Licensee/ Utilities and IPP will pay the difference of Unscheduled Interchange charges (UI charges) at the time of injection and at the time of withdrawal. However, withdrawal of banked power should not be allowed during peak and Time of Day (TOD) hours. If the banked energy is not utilized within a period of twelve months from the date of power banked with the concerned power utilities/ licensee, it will automatically lapse and no charges shall be paid in lieu of such power.

The banking facility shall be allowed for the grid connected rooftop solar power projects on the same pattern as per MW scale projects.

4.7 Renewable Energy Certificate

A generating company engaged in generation of electricity from Solar Power Plant shall be eligible to avail the Renewable Energy Certificates as per regulations of the Central Electricity Regulatory Commission.

4.8 Exemption from Land use approval, External Development Charges, scrutiny fee and infrastructure development charges.

These projects of MW scale shall not require any change of Land Use approval from Town & Country Planning Department. The project shall also be exempted from External Development Charges (EDC), scrutiny fee and infrastructure development charges but if special service is required for the solar project then EDC charges shall be charged on pro-rata basis. The details of such projects will be intimated to the Town & Country Planning Department.

However, after the expiry of purchase power agreement period or when plant ceases to operate on the land, land use will revert to the original (time of installation of plant) master plan of the area/city/town (i.e. it will convert to the original status of land).

4.9 Exemption of Environment Clearance

These projects shall not require any clearance from the Haryana Pollution Control Board.

4.10 Exemption of the Clearance from Forest Department

Wherever not expressly prohibited and wherever possible, if clearance from Forest Department, Haryana under their Act/Notification is required the same will be facilitated by single window authority clearance agency of the Renewable Energy Department.

4.11 Exemption in Stamp Duty for lease of land for projects

These projects of MW scale shall be provided 100% exemption from payment of fee and stamp duty charges for registration of rent/lease deed for the land required for setting up of these projects.

4.12 Use of unutilized space

The developers setting up the ground mounted MW scale solar power plants may also use the space in between the installed solar panels for commercial floriculture/horticulture related activities provided that it does not affect solar power generation and also keeping in view all the safety and security measures as required for the installed equipments as per the provisions of Electricity Act, 2003.

4.13 Metering

Metering equipments for the power generation & its sale will be installed at site by the user at their own cost as per specification of Power Utilities of State/ HERC Grid Code/ Central Electricity Authority (Installation and Operation of meters) Regulations, 2006 and its subsequent amendments.

The testing of these equipments will be carried out by Power utilities, at the user's cost. Power utilities will develop necessary infrastructure at locations where more than one project is installed.

The Metering equipments and the allied equipments be installed in the following manner:-

- (a) Main meter at the interconnection point shall be provided by the IPP.
- (b) Check meter at the interconnection point shall be provided by the Nigam/DISCOM.
- (c) Main Meter at the substation of the Nigam/DISCOM shall be provided by the Nigam/DISCOM.
- (d) Check meter at the substation of the Nigam shall be provided by the company.

Metering of the power produced shall be done at substation of the Nigam/DISCOM.

4.14 Tenure of Power Purchase Agreement

The Power Purchase Agreement (PPA) to be signed between IPP and HPPC shall be valid for a period of 25 years. After this period, the PPA can be renegotiated between the power producer and concerned power utilities/ licensee.

4.15 Earnest Money Deposit

For grid connected solar power projects, installed for sale of power, the application shall be accompanied with the Earnest Money Deposit (EMD) of Rs.2.00 lacs per MW (Rs.200/- per KW) in the shape of demand draft, which shall be refunded after signing of PPA. However, if the bidder/developer fails/refuses to deposit the security deposit or fails/refuses to sign the PPA within the stipulated time, the EMD of the bidder will be forfeited.

4.16 Minimum Equity to be held by the Promoter

The project developer may be individual/company/firm/group of companies or a Joint venture/Consortium of maximum 4 partners having minimum 51% share holding of leading partner.

The grid connected solar project developer(s) shall provide the information about the Promoters and their shareholding in the company, along with the bid document, indicating the leading shareholder. No change in the leading shareholder, developing the Solar Power Project, shall be permitted from the date of submitting the application and till one year of execution of the project. This shall not be applicable to the Solar Power Projects developed by the public limited companies. Thereafter, any change may be undertaken only with information to Renewable Energy Department/HAREDA or HPPC, as the case may be.

Further, only new plant and machinery shall be allowed under this policy.

CHAPTER-V**INITIATIVES**

To promote rooftop solar power projects, the State Government has taken the following initiatives:

5.1 Mandatory installation of Solar power plants

The State Government *vide* its notification dated 03.09.2014 has mandated installation of solar power plant of 3% to 5% of connected load for categories of all residential buildings built on a plot size of 500 Square

Yards and above, all Government and private Educational Institutes, Schools, Colleges, Hostels, Technical/Vocational Education Institutes, Universities, Offices having connected load of 30 Kilo Watt (KW) and above all private Hospitals and Nursing Homes, Industrial Establishments, Commercial Establishments, Malls, Hotels, Motels, Banquet Halls and Tourism Complexes, having connected load of 50 Kilo Watt (KW) and above, all new Housing Complexes, developed by Group Housing Societies, Builders, Housing Boards, on a plot size of 0.5 Acre and above and all water lifting stations of Irrigation Department.

In the residential sector, its mandatory enforcement shall be for the new residential buildings only whereas the installation of the rooftop solar power plants in the existing residential buildings shall be promoted by providing financial incentives. For other sectors even the existing buildings will be covered.

If the user covered under the mandatory provision is not installing the rooftop solar power plant as per the notification, then penalty shall be imposed as per Government rules and regulations.

5.2 Net Metering Facility

The grid connected rooftop solar photovoltaic systems of capacity equivalent to the sanctioned load can be installed for the captive use, for which the net-metering facility shall be provided as per the Haryana Electricity Regulatory Commission regulations. The electricity generated from such systems shall be cumulatively adjusted at 90% of the electricity consumption during the financial year. In addition, during the FY 2015-16 an incentive @ 25 paise per unit shall also be provided in their bills on the solar power thus generated. The incentive payable under these Regulations shall be reviewed by the Commission every year along with ARR/Tariff petition for that year and the incentive payable accordingly for FY 2016-17 onwards.

The amendments issued by HERC, in this context, from time to time shall be followed.

5.3 Lease of Government buildings/Land

The rooftop space available in the Government organization, institutions, buildings or vacant land of the same can also be provided on lease/rent to the Independent Power Producer/ RESCO developer for setting up of solar power projects.

For such sites the lease/rent rate shall be decided by a Committee of Deputy Commissioner of concerned district, PWD (B&R) Department and the Department owning the building. The developer can also supply/provide the power for the captive use of the premises where the system is installed along with net meter and can sell the remaining power to HPPC on the minimum last tariff discovered and conveyed by HPPC or to third party as per the HERC Regulations.

5.4 Agriculture Solar Pump sets

The State in collaboration with the Central Government / MNRE, Government of India will promote the installation of Agricultural Solar Powered Pump sets through subsidy support (if applicable) to meet water/ irrigation energy needs. The surplus power generation from the solar pump sets may be bought by the HPPC at APPC rate of the year. The solar energy thus generated and exported shall also be credited towards meeting the RPO of the DISCOM.

CHAPTER-VI

GUIDELINES

6.1 Technical Requirements

The Independent Power Producers and the users producing power from Grid tied /Grid connected solar power plants as well as users of off-grid solar devices would be required to strictly adhere to the national/international standards/specifications specified by the Ministry of New & Renewable Energy, Government of India or as amended from time to time and relevant IEC/ BIS standards and / or applicable standards as specified by the Central Electricity Authority/ Bureau of Energy Efficiency, as the case may be.

The independent power producers have also to comply with the HERC Renewable Energy Regulations, 2010, as amended from time to time.

6.2 Other schemes of MNRE, Government of India

The setting up of solar power projects shall also be promoted under various programmes implemented under Jawahar Lal Nehru National Solar Mission (JNNSM) of the Ministry of New & Renewable Energy, Government of India, like Viability Gap Funding (VGF), scheme for unemployed youth/ farmers, bundling

scheme of National Vidyut Vyopar Nigam Ltd. (NVVNL)/National Thermal Power Corporation (NTPC) and rooftop solar power plants programme, as per their guidelines, from time to time.

6.3 Nodal Agency

Renewable Energy Department is the nodal agency for the implementation of the Haryana Solar Power Policy-2016 on behalf of the Government of Haryana.

All project developers shall be required to submit monthly reports with regard to parameter like energy generated, revenue earned, power factor and plant load factor achieved, reasons for non-achievement of full generation and any other information so called for by Renewable Energy Department/HAREDA so as to maintain and update data bank on solar power generation in the State and also for the purpose of monitoring of generation under RPO regulations.

6.4 Amendments/ Relaxation/ Interpretation of provisions of the Policy

Secretary to Government of Haryana, Renewable Energy Department shall have the powers to amend / relax / issue clarification, if any, on any matter related to interpretation of any provisions under the policy in consultation with the concerned Government Departments / Agencies.

CHAPTER-VII

GLOSSARY

7.1 Following expressions used in the Policy would have meanings assigned to them as defined hereunder:-

- i. "Act" means Electricity Act, 2003, including amendments there to.
- ii. "APPC" means Average Power Purchase Cost.
- iii. "Canal" means feeder, canal, rajbahas, minors, drains, channels and Minor Irrigation Tubewells, Corporation (MITC) Nalas
- iv. "CEA" means Central Electricity Authority.
- v. "CERC" means the Central Electricity Regulatory Commission of India, constituted under Sub-section (1) of Section 76 of the Electricity Act, 2003, or its successors.
- vi. "Central Agency" means National Load Dispatch Centre (NLDC) as designated by the Central Electricity Regulatory Commission *vide* order dated 29.01.2010 for the purposes of the REC Regulations.
- vii. "Conventional Power Plants" means lignite; coal, fossil fuel or gas based thermal generating power stations and hydro generating stations of more than 25 MW capacities.
- viii. "DISCOM of Haryana" means a distribution licensee, such as UHBVNL, Panchkula, DHBVNL, and Hisar.
- ix. "FDPR" means Feasible Detailed Project Report.
- x. "Government" and "State" means the Government of Haryana and the State of Haryana respectively.
- xi. "IREDA" means Indian Renewable Energy Development Agency.
- xii. "Licensee" includes a person deemed to be a licensee under Section 14 of the Act.
- xiii. "MNRE" means Ministry of New and Renewable Energy, a Central Government Ministry responsible to develop and deploy new and renewable energy for supplementary energy requirement of the country.
- xiv. "MOU" means Memorandum of Understanding.
- xv. "National Solar Mission or Solar Mission" means Jawaharlal Nehru National Solar Mission 2009 launched by Government of India.
- xvi. "NTPC" means National Thermal Power Corporation.
- xvii. "NVVNL" means National Vidyut Vyopar Nigam Ltd.
- xviii. "Nodal agency" means Haryana Renewable Energy Development Agency (HAREDA) or any other agency designated by Government of Haryana for promotion of electricity generation from renewable energy sources.
- xix. "PPA" means Power Purchase Agreement.
- xx. "REC Regulation" or "CERC REC Regulation" means Central Electricity Regulatory

Commission (Terms & Condition for recognition and issuances of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulation, 2010 notified by CERC *vide* Notification dated 14.1.2010 and amended from time to time.

- xxi. “Renewable Energy Certificate” or “REC” means the Renewable Energy (Solar) Certificate issued by the Central Agency in accordance with the procedure prescribed by it and under the provision specified in the Central Electricity Regulatory Commission (Terms & Conditions for recognition and issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulation, 2010.
- xxii. “HERC”/“Commission” means Haryana Electricity Regulatory Commission.
- xxiii. “RPO” means Renewable Purchase Obligation.
- xxiv. “SECI” means Solar Energy Corporation of India.
- xxv. “Solar Power Producer” means an entity, which owns facilities to generate electric power for sale to DISCOM of Haryana/Licensees/NVVN /NTPC/ to third party/captive use.
- xxvi. “Solar Plant/Solar Power Plant” means a power plant or system utilizing solar energy through solar photo-voltaic or concentrated solar thermal devices including its integration into conventional fossil fuel for generating of electricity.
- xxvii. “Solar PV Power Plant” means the Solar Photo Voltaic (SPV) Power Plant that uses sunlight for direct conversion into electricity through Photo Voltaic technology.
- xxviii. “Tariff” means the schedule of charges for generation, transmission, wheeling and supply of electricity together with terms and conditions for application thereof.
- xxix. “TOD” means Time of Day in Hours.
- xxx. “UI Charges” means unscheduled Interchange charges.
- xxxi. “EHV” means Extra High Voltage.
- xxxii. “HV” means High Voltage.
- xxxiii. “MW” means Mega Watt.
- xxxiv. “KWp” means Kilo Watt Peak.
- xxxv. “LOI” means Letter of Intent.
- xxxvi. “HPPC” means Haryana Power Purchase Centre.

7.2.1 All other words and expressions used herein and not defined shall have the meanings respectively assigned to them in The Electricity Act-2003.

ANKUR GUPTA,
Principal Secretary to Government Haryana,
Renewable Energy Department, Chandigarh.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

38-2016/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, MARCH 14, 2016 (PHALGUNA 24, 1937 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 14th March, 2016

No.1-HLA of 2016/5.— The Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2016, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 1- HLA of 2016.

THE HARYANA MUNICIPAL (AMENDMENT) BILL, 2016

A

BILL

further to amend the Haryana Municipal Act, 1973.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows :-

1. This Act may be called the Haryana Municipal (Amendment) Act, 2016.
2. In clause (d) of sub-section (1) of section 13A of the Haryana Municipal Act, 1973,-
 - (i) for the sign ‘.’ existing at the end, the sign and word ‘; or’ shall be substituted;
 - (ii) after clause (d), the following clauses shall be added, namely:-
 - “(e) if he has been convicted or charges have been framed against him by a court in a criminal case for an offence, punishable with imprisonment for not less than ten years; or
 - (f) if he fails to pay an arrear of any kind due to him to any Primary Agriculture Co-operative Society, District Central Co-operative Bank and District Primary Co-operative Agriculture Rural Development Bank; or
 - (g) if he fails to pay arrears of electricity bills; or

Short title.

Amendment of section 13A of Haryana Act 24 of 1973.

(h) If he has not passed matriculation examination or its equivalent examination from any recognized institution/board:

Provided that in case of a woman candidate or a candidate belonging to Scheduled Caste, the minimum qualification shall be middle pass:

Provided further that in case of a woman candidate belonging to Scheduled Caste, the minimum qualification shall be 5th pass; or

(i) if he fails to submit a self declaration to the effect that he has a functional toilet at his place of residence.”.

Repeal and
savings.

3. (1) The Haryana Municipal (Amendment) Ordinance, 2016 (Haryana Ordinance No. 2 of 2016), is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

1. The amendment of the Haryana Municipal Act, 1973 aims to strengthen the Urban Local Bodies, the third tier of the Governance and improving efficiency, transparency and accountability by making education as a necessary qualification for the office bearers of Urban Local Bodies. With the 74th Constitutional amendment, the Urban Local Bodies are being vested with more powers and funds which requires the Members of Urban Local Bodies to discharge executive functions like planning, implementation of infrastructural projects, resource allocations, disbursements of funds, purchase of goods, regulation of activities in urban area and laying down of procedures for their day to day functioning. Prescribing minimum standards of education will not only help in augmenting performance of the Members of Urban Local Bodies, but also reduce chances of them being misled and ensure their accountability. In view of good literacy rate in the State, election of educated candidates for Urban Local Bodies will prove to be a catalyst for faster and sustainable development of cities.
2. Elected members of ULBs are leaders of society and their conduct should be impeccable.
3. There are instances where persons have been let off because of shortcomings in the investigation process and / or non-fulfilment of technical specifications like absence of sanction of prosecution or lack of strong prosecution by the public prosecutor. Therefore, conviction or charges framed against any person by a court in a criminal case for an offence, punishable with imprisonment for not less than ten years is being made as a disqualification for contesting the elections of Urban Local Bodies.
4. The Urban Local Bodies are also expected to lead social change and foster economic development in the cities. All this requires educated and informed leadership, which can lead by example. Therefore, default of payment of electricity bill or of loans of co-operative Institutions is being made as disqualification for contesting the elections of Urban Local Bodies.
5. The appropriate sanitation arrangements in the residential areas of urban population is the main attention of the time and in this scenario the provision of functioning toilets in each and every house is must. To boost and encourage such type of provision of toilet must be started from the elected representative of the Urban Local Bodies. Therefore, non provision of functional toilet at the place of residence of a candidate is being made as disqualification.

KAVITA JAIN,
Urban Local Bodies Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 14th March, 2016.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2016 का विधेयक संख्या 1-एच0एल0ए0

हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2016

हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973,

को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. यह अधिनियम हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2016, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।
2. हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 13क की उपधारा (1) के खण्ड (घ) में,—
 - (i) अन्त में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, "; या" चिह्न तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
 - (ii) खण्ड (घ) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“(ङ) यदि वह किसी आपराधिक मामले में कारावास जो दस वर्ष से कम न हो, से दण्डनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा सिद्धदोष किया गया है या उसके विरुद्ध आरोप लगाए गए हों ; या

(च) यदि वह किसी प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटी, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा जिला प्राथमिक सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक के उसकी ओर देय किसी प्रकार के बकाया का भुगतान करने में असफल रहता है ; या

(छ) यदि वह बिजली बिलों के बकायों का भुगतान करने में असफल रहता है ; या

(ज) यदि उसने किसी मान्यताप्राप्त संस्था / बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा पास न की हो :

परन्तु महिला उम्मीदवार या अनुसूचित जाति से सम्बन्धित उम्मीदवार की दशा में, न्यूनतम योग्यता मिडल पास होगी :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जाति से सम्बन्धित महिला उम्मीदवार की दशा में, न्यूनतम योग्यता पांचवीं पास होगी ; या

(झ) यदि वह इस आशय की स्वतः घोषणा प्रस्तुत करने में असफल रहता है कि उसके अपने निवास स्थान पर कार्यशील शौचालय है ।”।
3. (1) हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2016 (2016 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 2), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है। निरसन तथा व्यावृत्ति।
 (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

1. हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 में संशोधन का उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों, जोकि शासन का तीसरा स्तर है, को मजबूत करना है तथा शहरी स्थानीय निकायों के पदाधिकारियों के लिये शिक्षा को एक आवश्यक योग्यता के रूप में बनाकर उनकी दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करना है। 74 वें संविधान संशोधन के द्वारा शहरी स्थानीय निकायों में अधिक शक्तियां व निधियां निहित की जा रही हैं, जिसके लिये शहरी स्थानीय निकायों के सदस्यों को नीतिगत, संरचनात्मक परियोजना को लागू करने, संसाधन आबंटन, निधि का भुगतान, वस्तुओं की खरीद, शहरों में गतिविधियों सम्बन्धी तथा दिन-प्रतिदिन सम्बन्धी प्रक्रियाओं जैसे अन्य कार्य करने पड़ते हैं। शिक्षा की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना केवल मात्र शहरी स्थानीय निकायों के सदस्यों की कार्यशैली में सुधार ही नहीं करेगा बल्कि उनके गुमराह करने के अवसरों में कमी लायेगा तथा उनकी जिम्मेवारी निर्धारित करेगा। राज्य की अच्छी साक्षरता दर के मध्यनजर शहरी स्थानीय निकायों के विभिन्न पदों पर शिक्षित उम्मीदवारों का चुनाव शहरों के दीर्घ कालिक विकास में गतिशीलता का उत्प्रेरक सिद्ध होगा।
2. शहरी स्थानीय निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधि समाज को नेतृत्व प्रदान करते हैं एवं उनका आचरण त्रुटिहीन होना चाहिये।
3. ऐसे उदाहरण हैं जहां व्यक्तियों को जांच प्रक्रिया में कमियों और/या तकनीकी विनिर्देशों के पूर्ण ना करने, जैसे कि अभियोजन की मंजूरी या सरकारी वकील द्वारा मजबूत अभियोजन की कमी के कारण मुक्त कर दिया जाता है। इसलिये, दोषसिद्धि या किसी आपराधिक मामले में कारावास जो दस वर्ष से कम ना हो, से दण्डनीय किसी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा आरोप लगाये गये हों, को शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने के लिये अयोग्यता बनाया जा रहा है।
4. शहरी स्थानीय निकाय शहरों के सामाजिक बदलाव व आर्थिक उन्नति के लिये अग्रगामी समझी जाती हैं। ये सभी शिक्षित और सचेतक नेतृत्व चाहती हैं जो उदाहरणीय हो। अतः बिजली के बिलों का बकाया तथा सहकारी संस्थाओं के ऋणों की अदायगी के दोषों को शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने के लिये अयोग्य बनाया जा रहा है।
5. शहरी जनसंख्या के आवासीय क्षेत्र में उचित सफाई प्रबन्धों का होना समय की मुख्य मांग है तथा इस परिदृश्य में प्रत्येक घर में शौचालय का चालू हालत में होना अति आवश्यक है। इस प्रकार शौचालय के प्रावधान को बढ़ावा एवं प्रोत्साहन देने हेतु यह शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से आरम्भ किया जाना आवश्यक है। इसलिये शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने हेतु किसी उम्मीदवार के घर पर चालू हालत में शौचालय का प्रावधान ना होने को, अयोग्यता बनाया जा रहा है।

कविता जैन,
शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 14 मार्च, 2016.

आर० के० नांदल,
सचिव।



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

38-2016/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, MARCH 14, 2016 (PHALGUNA 24, 1937 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 14th March, 2016

No. 2-HLA of 2016/4.— The Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2016, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 2- HLA of 2016

THE HARYANA MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT)

BILL, 2016

A

BILL

further to amend the Haryana Municipal Corporation Act, 1994.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Act, 2016.
2. In clause (n) of sub-section (2) of section 8 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994,—
 - (i) for the sign ‘.’ existing at the end, the sign and word ‘; or’ shall be substituted;
 - (ii) after clause (n), following clauses shall be inserted, namely:—
 - “(o) if he has been convicted or charges have been framed against him by a court in a criminal case for an offence, punishable with imprisonment for not less than ten years; or
 - (p) if he fails to pay an arrear of any kind due to him to any Primary Agriculture Co-operative Society, District Central Co-operative Bank and District Primary Co-operative Agriculture Rural Development Bank; or
 - (q) if he fails to pay arrears of electricity bills; or

Short title.

Amendment of section 8 of Haryana Act 16 of 1994.

Price : Rs. 5.00

(4029)

- (r) if he has not passed matriculation examination or its equivalent examination from any recognized institution/board:

Provided that in case of a woman candidate or a candidate belonging to Scheduled Caste, the minimum qualification shall be middle pass:

Provided further that in case of a woman candidate belonging to Scheduled Caste, the minimum qualification shall be 5th pass; or

- (s) if he fails to submit a self declaration to the effect that he has a functional toilet at his place of residence.”.

Repeal and
savings.

3. (1) The Haryana Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2016 (Haryana Ordinance No. 3 of 2016), is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

1. The amendment of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 aims to strengthen the Urban Local Bodies, the third tier of the Governance and improving efficiency, transparency and accountability by making education as a necessary qualification for the office bearers of Urban Local Bodies. With the 74th Constitutional amendment, the Urban Local Bodies are being vested with more powers and funds which requires the Members of Urban Local Bodies to discharge executive functions like planning, implementation of infrastructural projects, resource allocations, disbursements of funds, purchase of goods, regulation of activities in urban area and laying down of procedures for their day to day functioning. Prescribing minimum standards of education will not only help in augmenting performance of the Members of Urban Local Bodies, but also reduce chances of them being misled and ensure their accountability. In view of good literacy rate in the State, election of educated candidates for Urban Local Bodies will prove to be a catalyst for faster and sustainable development of cities.
2. Elected member of ULBs are leaders of society and their conduct should be impeccable.
3. There are instances where persons have been let off because of shortcomings in the investigation process and/ or non-fulfilment of technical specifications like absence of sanction of prosecution or lack of strong prosecution by the public prosecutor. Therefore, conviction or charges framed against any person by a court in a criminal case for an offence, punishable with imprisonment for not less than ten years is being made as a disqualification for contesting the elections of Urban Local Bodies.
4. The Urban Local Bodies are also expected to lead social change and foster economic development in the cities. All this requires educated and informed leadership, which can lead by example. Therefore, default of payment of electricity bill or of loans of co-operative Institutions is being made as disqualification for contesting the elections of Urban Local Bodies.
5. The appropriate sanitation arrangements in the residential areas of urban population is the main attention of the time and in this scenario the provision of functioning toilets in each and every house is must. To boost and encourage such type of provision of toilet must be started from the elected representative of the Urban Local Bodies. Therefore, non provision of functional toilet at the place of residence of a candidate is being made as disqualification.

KAVITA JAIN,
Urban Local Bodies Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 14th March, 2016.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2016 का विधेयक संख्या 2-एच.एल.ए.

हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2016

हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994,

को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम।

1994 के हरियाणा
अधिनियम 16
की धारा 8 का
संशोधन।

1. यह अधिनियम हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2016, कहा जा सकता है।
2. हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 8 की उपधारा (2) के खण्ड (ढ) में,—
 - (i) अन्त में विद्यमान “।” चिह्न के स्थान पर, “; या” चिह्न तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
 - (ii) खण्ड (ढ) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“(ण) यदि वह किसी आपराधिक मामले में कारावास जो दस वर्ष से कम न हो, से दण्डनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा सिद्धदोष किया गया है या उसके विरुद्ध आरोप लगाए गए हों ; या

(त) यदि वह किसी प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटी, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा जिला प्राथमिक सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक के उसकी ओर देय किसी प्रकार के बकाया का भुगतान करने में असफल रहता है ; या

(थ) यदि वह बिजली बिलों के बकायों का भुगतान करने में असफल रहता है ; या

(द) यदि उसने किसी मान्यताप्राप्त संस्था/ बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा पास न की हो :

परन्तु महिला उम्मीदवार या अनुसूचित जाति से सम्बन्धित उम्मीदवार की दशा में, न्यूनतम योग्यता मिडल पास होगी :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जाति से सम्बन्धित महिला उम्मीदवार की दशा में, न्यूनतम योग्यता पांचवीं पास होगी ; या

(ध) यदि वह इस आशय की स्वतः घोषणा प्रस्तुत करने में असफल रहता है कि उसके अपने निवास स्थान पर कार्यशील शौचालय है ।”।

निरसन तथा
व्यावृत्ति।

3. (1) हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2016 (2016 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 3), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

1. हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 में संशोधन का उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों, जोकि शासन का तीसरा स्तर है, को मजबूत करना है तथा शहरी स्थानीय निकायों के पदाधिकारियों के लिये शिक्षा को एक आवश्यक योग्यता के रूप में बनाकर उनकी दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करना है। 74 वें संविधान संशोधन के द्वारा शहरी स्थानीय निकायों में अधिक शक्तियां व निधियां निहित की जा रही हैं, जिसके लिये शहरी स्थानीय निकायों के सदस्यों को नीतिगत, संरचनात्मक परियोजना को लागू करने, संसाधन आबंटन, निधि का भुगतान, वस्तुओं की खरीद, शहरों में गतिविधियों सम्बन्धी तथा दिन-प्रतिदिन सम्बन्धी प्रक्रियाओं जैसे अन्य कार्य करने पड़ते हैं। शिक्षा की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना केवल मात्र शहरी स्थानीय निकायों के सदस्यों की कार्यशैली में सुधार ही नहीं करेगा बल्कि उनके गुमराह करने के अवसरों में कमी लायेगा तथा उनकी जिम्मेवारी निर्धारित करेगा। राज्य की अच्छी साक्षरता दर के मध्यनजर शहरी स्थानीय निकायों के विभिन्न पदों पर शिक्षित उम्मीदवारों का चुनाव शहरों के दीर्घ कालिक विकास में गतिशीलता का उत्प्रेरक सिद्ध होगा।
2. शहरी स्थानीय निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधि समाज को नेतृत्व प्रदान करते हैं एवं उनका आचरण त्रुटिहीन होना चाहिये।
3. ऐसे उदाहरण हैं जहां व्यक्तियों को जांच प्रक्रिया में कमियों और/या तकनीकी विनिर्देशों के पूर्ण ना करने, जैसे कि अभियोजन की मंजूरी या सरकारी वकील द्वारा मजबूत अभियोजन की कमी के कारण मुक्त कर दिया जाता है। इसलिये, दोषसिद्धि या किसी आपराधिक मामले में कारावास जो दस वर्ष से कम ना हो, से दण्डनीय किसी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा आरोप लगाये गये हों, को शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने के लिये अयोग्यता बनाया जा रहा है।
4. शहरी स्थानीय निकाय शहरों के सामाजिक बदलाव व आर्थिक उन्नति के लिये अग्रगामी समझी जाती हैं। ये सभी शिक्षित और सचेतक नेतृत्व चाहती हैं जो उदाहरणीय हो। अतः बिजली के बिलों का बकाया तथा सहकारी संस्थाओं के ऋणों की अदायगी के दोषी को शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने के लिये अयोग्य बनाया जा रहा है।
5. शहरी जनसंख्या के आवासीय क्षेत्र में उचित सफाई प्रबन्धों का होना समय की मुख्य मांग है तथा इस परिदृश्य में प्रत्येक घर में शौचालय का चालू हालत में होना अति आवश्यक है। इस प्रकार शौचालय के प्रावधान को बढ़ावा एवं प्रोत्साहन देने हेतु यह शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से आरम्भ किया जाना आवश्यक है। इसलिये शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने हेतु किसी उम्मीदवार के घर पर चालू हालत में शौचालय का प्रावधान ना होने को, अयोग्यता बनाया जा रहा है।

कविता जैन,
शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 14 मार्च, 2016.

आर० के० नांदल,
सचिव।